



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, बुधवार, 5 मार्च, 2008 / 15 फाल्गुन, 1929

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

27<sup>th</sup> February, 2008

**No UD -F(5)3/2003-11.**— Whereas the Governor of Himachal Pradesh intend to issue a notification under sub section (1) of Section 3 of the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act , 1993 to the effect that no person shall –(a) engage in or employ for or permit to be engaged in or employed for any other person for manually carrying human excreta or (b) construct or maintain a dry latrine;

And whereas as per provision of sub section (2) of Section 3 of the aforesaid Act, a notification under sub – section (1) can not be issued unless:-

- (iv) a notice of not less then 90 days of its intention is given;
- (v) adequate facilities for the use of water seal latrines in that area exist ;  
and

- (vi) it is necessary or expedient to do so for the protection and improvement of environment or public health in that area ;

Now , therefore, as per requirement of sub-section (2) of Section 3 of the Act, 90 days notice is given from the date of publication of this notification in the official Gazette, declaring the intention of the State Govt. to issue notification under sub-section (1) of Section 3 where after the provision of sub-section (1) of Section 3 of the Act shall be made applicable in the areas of all Municipality Corporation / Municipality Councils /Nagar Panchayats in Himachal Pradesh, where adequate facilities for the use of water seal latrines exists.

If any interested resident of the Municipal Areas has any objection or suggestions in relation to this notice he/she may send the same to the Additional Chief Secretary(Urban Development) to the Govt. of Himachal Pradesh within the specified period of 90 days.

The objections/suggestions, if any , so received shall be taken into consideration by the Government before issuing the final Notification under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition )Act, 1993.

By order,  
Sd/-  
Addl. Chief Secretary.

## शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

27 फरवरी, 2008

**संख्या: यू0डी0-एफ0(5)3 / 2003-11.-** हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का, सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (1993 का 46) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन, इस प्रभाव की अधिसूचना जारी करने का आशय है कि कोई भी व्यक्ति-(क) मानव मल-मूत्र को हाथों से ढाने के लिए न तो किसी अन्य व्यक्ति को काम पर लगाएगा या न ही नियोजित करेगा और न ही उसमें काम पर लगाने या नियोजित करने की अनुज्ञा देगा या (ख) न ही शुष्क शौचालय का सन्निर्माण या अनुरक्षण करेगा ; और

और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्ध के अनुसार उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जा सकती जब तक कि:-

- (i) इसके आशय की सूचना का कम से कम नब्बे दिन का नोटिस न दे दिया गया हो;
- (ii) उस क्षेत्र में वाटर सील शौचालय के उपयोग के लिए पर्याप्त प्रसुविधाएं उपलब्ध न हो; और
- (iii) उस क्षेत्र में पर्यावरण या लोक स्वास्थ्य के संरक्षण और सुधार के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन न हो;

अतः अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) की अपेक्षा के अनुसार धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार के अधिसूचना जारी करने के आशय की घोषणा का, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की

तारीख से, नब्बे दिन का नोटिस दिया जाता है जिस के पश्चात् अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्ध हिमाचल प्रदेश में उस नगर निगम तथा उन समस्त नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों को लागू समस्त क्षेत्रों में, जहां वाटर सील शौचालय के लिए पर्याप्त प्रसुविधाएं उपलब्ध हैं, लागू किए जाएंगे।

इस नोटिस के सम्बन्ध में यदि नगरपालिका क्षेत्रों का हितबद्ध निवासी का कोई आक्षेप या सुझाव है तो वह उसे/उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को नब्बे दिन की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेज सकेगा/सकेगी।

इस प्रकार प्राप्त आक्षेप (पों)/सुझाव (वों), यदि कोई हों, पर सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निमार्ण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अधीन अन्तिम अधिसूचना जारी करने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/—  
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

---

## LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 4<sup>th</sup> March, 2008*

**No. Shram (A) 4- 1/ 2006.**— The Governor of Himachal Pradesh is pleased to withdraw the nominations of non- officials members of State Committee on Employment to advise the Department of Labour and Employment on problems relating to employment, creation of employment opportunities and the working of the National Employment Service in Himachal Pradesh constituted vide this department's notification of even no. dated 24/ 9/ 2007 with immediate effect.

By order,  
Sd/-  
Additional Chief Secretary- cum-  
Pr. Secretary.

---

## HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA

### NOTIFICATION

*Shimla, the February 28<sup>th</sup> 2008*

**No.HPERC/609B.**— In exercise of the powers conferred by sub-sections (6) and (7) of section 42 and section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, after previous publications, hereby makes the following regulations further to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory

Commission (Electricity Ombudsman) Regulations, 2004, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary), dated 5th April, 2004:-

## REGULATIONS :

**1. Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) (Fourth Amendment) Regulations, 2008.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Amendment of regulation 2.**— For clause (4) of regulation 2 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) Regulations, 2004 (hereinafter called “the said regulations”), the following clause (4) shall be substituted, namely,-

“(4) “complainant” means—

- (a) a consumer of electricity supplied by the licensee, including applicants for new connections;
- (b) any person whose electricity connection is disconnected;
- (c) a voluntary consumer association registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or under any other law for the time being in force;
- (d) one or more consumer, where there are numerous consumers having the same interest;
- (e) in case of death of a consumer his legal heirs or representatives;”.

**3. Amendment of regulations 7,8,9,10,11,12 and 13.**— In regulations 7,8,9,10,11,12 and 13 of the said regulations for the words “aggrieved party” or “aggrieved persons”, or “any person”, or “persons”, wherever these occur, the words “complainant” shall be substituted.

**4. Amendment of regulation 11.**— In sub-regulation (4) of regulation 11 of the said regulations, for the words “The parties to the proceedings will”, the words “The distribution licensee shall” be substituted.

**5. Amendment of regulation 12.**— In sub-regulation (3) of regulation 12 of the said regulations for the words “the parties to the proceedings will”, the words, “the licensee shall”, be substituted.

**6. Omission of regulation 12-A.**— The existing regulation 12-A of the said regulations shall be omitted.

**7. Amendment of Form-I.**— In the existing Form-I to the said regulations for the word “Consumer” wherever it occurs, the word “Complainant” shall be substituted.

**8. Omission of Form I-A.**— The existing Form 1-A to the said regulations shall be omitted.

**9. Amendments in the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2005.—**

- (a) in sub-regulation (1) of regulation 58, the word and sign comma “appeal,” shall be omitted;
- (b) in regulation 59, item (6) shall be omitted; and
- (c) in the Schedule, item 13-A shall be omitted.

By order,  
Sd/-  
Secretary.

विद्युत विनियम प्रदेशामक आयोग शिमला

अधिसूचना

शिमला—171002, 28 फरवरी, 2008

**संख्या: एच0पी0ई0आर0सी0/609B.—** असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, दिनांक 5 अप्रैल, 2004 में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओम्बुड्समैन) विनियम, 2004 में और संशोधन करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (36 का 2003) की धारा 42 की उप-धारा (6) तथा (7) तथा धारा 181 के साथ पठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, पूर्व प्रकाशन के उपरान्त, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:—

**विनियम**

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओम्बुड्समैन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2008 है।

(2) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

**2. विनियम 2 का संशोधन.—** हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओम्बुड्समैन) विनियम, 2004 (जिन्हें इसमें “उक्त विनियम” कहा गया है) के विनियम 2 के खण्ड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (4) प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

(4) “शिकायतकर्ता” का अर्थ है—

(क) नये संयोजनों के लिए आवेदकों सहित वह उपभोक्ता, जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय की हो;

(ख) ऐसा व्यक्ति जिसका विद्युत संयोजन काट दिया हो;

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अधीन पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ; या

(घ) एक या अधिक उपभोक्ता, जहां समान हित वाले बहुत सारे उपभोक्ता हों;

(ङ.) किसी उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में, उसका विधिक वारिस अथवा प्रतिनिधि;"।

3. **विनियम 7,8,9,10,11,12 तथा 13 का संशोधन.**— उक्त विनियमों के विनियम 7,8,9,10,11,12 तथा 13 में शब्द "व्यथित पक्षकार" या "व्यथित व्यक्ति" या "व्यक्ति" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "शिकायतकर्ता" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. **विनियम 11 का संशोधन.**— उक्त विनियमों के विनियम 11 के उप-विनियम (4) में, शब्द "पक्षकार" के स्थान पर शब्द "वितरण अनुज्ञप्तिधारी" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. **विनियम 12 का संशोधन.**— उक्त विनियमों के विनियम 12 में उप-विनियम (3) में शब्द "पक्षकार" के स्थान पर शब्द "अनुज्ञप्तिधारी" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6. **विनियम 12-क का लोप.**— उक्त विनियमों के विनियम 12-क का लोप किया जाएगा।

7. **प्ररूप-क का संशोधन.**— उक्त विनियमों के प्ररूप-क में शब्द "उपभोक्ता", जहां कहीं भी आया है, के स्थान पर शब्द "शिकायतकर्ता" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8. **प्ररूप 1-क का लोप.**— उक्त विनियमों के प्ररूप-1-क का लोप किया जाएगा।

9. **हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारवार संचालन) विनियम, में संशोधन.**—

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारवार संचालन), 2005 विनियम, में—

(क) विनियम 58 के उप-विनियम (1) में शब्द व चिन्ह "अपील," का लोप किया जाएगा;

(ख) विनियम 59 में मद (6) का लोप किया जाएगा; तथा

(ग) अनुसूची में मद 13-क का लोप किया जाएगा।

आदेश द्वारा

हस्ता/-

सचिव।

### वहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचनाएं

3 मार्च, 2008

**संख्या : विद्युत-छ-(5)-27/2007.**— यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि पब्लर वैली पावर कारपोरेशन लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः उप मुहाल बिजौरी, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0प्र0 में सावड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना के सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव: एतद्वारा

यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, थिसिल बैंक भवन, शिमला-3 के समक्ष अपनी आपति दर्ज कर सकता है।

### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
शिमला	रोहडू	बिजौरी	2333 / 1	0-01-65
			2333 / 3	0-02-10
			2333 / 5	0-02-28
			2333 / 7	0-04-79
			2333 / 1 / 2	0-01-44
			2333 / 1 / 4	0-01-48
			कुल कित्ता-6	कुल रकबा-0-13-74 हैक्टेयर

-----  
29 फरवरी, 2008

**संख्या: विद्युत.-छ-(5)-24/2007.-** यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मै0 न्यूज़िवीडू सीड्स लि0 905, नवम् मंजिल, कंचन जंगा बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड़, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक कम्पनी है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल जांगलिक, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0प्र0 में टांगनू रुमाई-II जल विद्युत परियोजना ( 6 मे0 वा0) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव: एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू अर्जन

समाहर्ता-एवं-उपमण्डाधिकारी (नागरिक), रोहडू जिला शिमला हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी				
जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
शिमला	चड़गांव	जांगलिक	352	00-06-80
			353	00-07-83
			409	00-42-74
			410	00-00-63
			420 / 1	00-06-24
			422	00-05-07
			423	00-14-11
			424	00-04-20
			425	00-01-08
			426	00-04-34
			427	00-02-44
			429 / 1	00-02-94
			430	00-02-62
			434	00-02-16
			431	00-19-31
			किता-15	रकबा: 01-22-51 हैक्टेयर

आदेश द्वारा,  
हस्ता / -  
प्रधान सचिव।

-----  
**OFFICE OF THE ASSISTANT REGISTRAR  
CO-OPERATIVE SOCIETIES SHIMLA-1**

**OFFICE ORDER**

*the 22<sup>th</sup> February, 2008*

**No.3-33/96-Coop,VII.**— In supersession of this office previous order No.4-14/97-Coop.-3455-56 dated 31.12.2007 and in continuation of this office order No.3-33/96-Coop.VII-2491-96 dated 28.8.2006 and in exercise of the powers conferred on me under section 79(1) of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No.3 of 1969) I, B.N. Sharma, Assistant Registrar, Coop. Societies, Shimla do hereby appoint, District Inspector, Coop. Societies, Shimla as the Liquidator of the Shimla Central Coop. Consumer Store Ltd., (Super Bazar) Shimla with immediate effect, in addition to his own duties to wind up the affairs of the aforesaid Super Bazar under the provisions of the ibid Act and the Rules made thereunder expeditiously in the time bound manner.

Sd/-  
B.N. SHARMA  
Assistant Registrar,  
Co-operative Societies ,  
Shimla Distt., Shimla-1.